सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23 अप्रैल, 1951 या एकीकरण की नियुक्ति के पश्चात में पद में कमी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है इसलिए अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता है। नए राज्य में उनकी पिछली सभी पोस्टिंग विशुद्ध रूप से संक्रमणकालीन और अस्थायी थी और जहाँ तक अनुबंध के अनुच्छेद XVI (1) का सवाल है, इसकी गारंटी पूरी हो चुकी है। अपील लागत सहित खारिज की जाती है।

याचिका खारिज की जाती है।

एस. आर.एम. ए.आर. एस. एसपी. सथप्पा चेट्टियार

बनाम

एस. आरएम. ए. आर. आर. एम. रामनाथन चेट्टियार

(भगवती, बी. पी. सिन्हा, जाफर इमाम, जे. एल. कपूर और गजेंद्रगढ़कर जे. जे.)

न्यायालय शुल्क, वाद के लिए प्रवर्तन की गणना- संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी- वादी द्वारा दावे का मूल्यांकन- अधिकार क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए मूल्य, न्यायालय-शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का VII), एस। 7 (IV) (बी)-वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 (1887 का VII), एस 8 के तहत समान होना चाहिए।

कोर्ट फीस अधिनियम के ७ (४) के तहत आने वाले मुकदमों में कोर्ट फीस की गणना उस मुल्यांकन पर निर्भर करती है जो वादी अपने विकल्प में अपने दावे पर लगाता है और एक बार जब वह अपने विकल्प का उपयोग करता है और अपने दावे को महत्व देता है तो ऐसा मुल्य मुकदमा मुल्याकंन अधिनियम की धारा ८ के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए भी लिए मुल्य होना चाहिए। इसलिए न्यायालय शुल्क के प्रयोजनों के लिए मुल्य ऐसे मुकदमें में क्षेत्राधिकार के प्रयोजनो के लिए मुल्य निधार्रित करता है, न ही इसके विपरित ।

जहां न्यायालय को पता चलता है कि मामला कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 7(IV)(बी), के अंतर्गत आता है और वादी ने अपने दावे को विशेष रूप से महत्व देना छोड़ दिया है इसलिए सामान्य तौर पर उसे अपने वाद में संशोधन करने और वह राशि निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिस पर वह अपने दावे का मूल्य निर्धारण करना चाहता है। क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए लगाया गया मूल्य जो न्यायालय शुल्क के प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता है,और उसे तदनुसार बदला जाना चाहिए।

करम इलाही बनाम मुहम्मद बशीर, ए.आई.आर. (1949) लाह. 116, संदर्भित।

परिणाम स्वरूप, वर्तमान मामले में जहां मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच की राय थी कि कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 7(IV)(बी) लागू होती है लेकिन फिर भी यह माना जाता है फिर भी माना जाता है कि अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए वादपत्र में दिए गए मूल्यांकन को न्यायालय शुल्क का उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन माना जाना चाहिए और अपीलकर्ता को वादपत्र और अपील के ज्ञापन दोनों पर उस न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, जिसके आधार पर आदेश रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता को उस राशि पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी गई, जिस पर उसने अपनी राहत का मूल्यांकन किया था।

आगे कहा गया मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए उच्च न्यायालय शुल्क नियम, 1933 के आदेश २ नियम १ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 12 मद्रास उच्च न्यायालय के मूल पक्ष पर लागू होती है और इसलिए यह क्षेत्राधिकार ग्रहण करने और उसके तहत उचित आदेश पारित करने के संदर्भ में डिवीजन बेंच के लिए खुला था।

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर किसी सबूत के अभाव में कि उन्हें इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश द्वारा आम तौर पर या विशेष रूप से सशक्त किया गया था,मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास न्यायालय

शुल्क अधिनियम की धारा 5 के तहत अंतिम आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1956 की सिविल अपील संख्या 203।

सी.एम.पी. में मद्रास उच्च न्यायालय के 25 जनवरी, 1955 के आदेशों की विशेष अनुमति द्वारा अपील 1954 का क्रमांक 9335 और 1953 का एस.आर. क्रमांक 55247

अपीलकर्ता की ओर से के.एस. कृष्णास्वामी अयंगर, आर. गणपति अय्यर और जी. गोपालकृष्णन।

प्रत्यर्थी की ओर से सी.के. दफ्तरी, भारत के सॉलिसिटर-जनरल और एम.एस.के. शास्त्री।

हस्तक्षेपकर्ता के लिए वेंकटकृष्णन और टी. एम. सेन।

28 नवंबर 1957 न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया

जस्टिस गजेंद्रगढ़कर- यह 25 जनवरी, 1955 को मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील है, जिसमें उनके वाद पत्र व अपील के ज्ञापन दोनो पर 15,00,000 रुपये के मूल्यांकन पर न्यायशुल्क का भुगतान करने का आहवान किया गया और यह कोर्ट फीस अधिनियम (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में वर्णित किया जाएगा) के प्रावधानों के तहत कानून के कुछ दिलचस्प सवाल उठाता है।

अपीलकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में 1951 का सिविल मुकदमा संख्या 311 दायर किया था। इस मुकदमे में, उन्होने संयुक्त परिवार की संपत्तियों के बंटवारे और प्रतिवादी द्वारा प्रबंधित संयुक्त परिवार की संपत्तियों के संबंध में एक खाते का दावा किया था।

अपीलकर्ता सुब्बैया चेट्टियार का पुत्र है। इस मामले में सुब्बैया को 1922 में लक्ष्मी अची ने गोद लिया था। लक्ष्मी अची प्रतिवादी के अविभाजित चाचा की विधवा थीं। गोद लेने के परिणामस्वरूप सुब्बैया अपने दत्तक परिवार में सहदायिक बन गया और, सुब्बैया के बेटे के रूप में अपीलकर्ता ने संयुक्त परिवार की संपत्तियों और संयुक्त परिवार की परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी का दावा किया और यही वह आधार था जिस पर अपीलकर्ता द्वारा अपने मुकदमें में विभाजन और खातो क दावा किया गया था। अपीलार्थी द्वारा अपने वाद में विभाजन एवं हिसाब-किताब का दावा किया गया था। वादपत्र में यह आरोप लगाया गया था कि सुब्बैया ने अपने हिस्से के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था और ट्रायल कोर्ट में डिक्री प्राप्त कर ली थी। प्रतिवादी ने उक्त डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की थी। अपील के लंबित रहने तक विवाद को पार्टियों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया और एक निर्दिष्ट राशि के भुगतान और कुछ निश्चित जमीनों पर कब्जा प्राप्त करने पर विचार करते हुए सुब्बैया ने संपत्तियों के संबंध में अपने और अपने बेटे, वर्तमान अपीलकर्ता के सभी दावों को निस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की। अपीलकर्ता के

अनुसार, इस समझौता लेनदेन ने अपीलकर्ता को बाध्य नहीं किया और इसलिए उसने अपने पिता और प्रतिवादी के बीच उक्त लेनदेन को नजर अंदाज करते हुए अपने हिस्से की वसूली का दावा किया। अपीलकर्ता द्वारा दायर वाद में अधिनियम की धारा 7(iv)(एफ) के तहत खातों के दावे का मूल्य रु 1,000/- रुपये आंका गया था और उक्त राशि पर मूल्य के आधार पर 112-7-0 न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया था। बंटवारे के लिए राहत के संबंध में अधिनियम की अनुसूची II की धारा 17-बी (मद्रास)के तहत अपीलकर्ता द्वारा 100 रूपये का भुगतान किया गया था । हालाँकि, क्षेत्राधिकार के उद्देश्य से अपीलकर्ता ने अपने हिस्से के मूल्य के रूप में १५०००००० रूपये दिए

ऐसा प्रतीत होता है कि रजिस्ट्री,वादपत्र की जांच करने पर, यह विचार करने के लिए इच्छुक थी कि वादी को न्यायालय शुल्क की धारा 7(v)के तहत विभाजन के दावे के संबंध में न्याय शुल्क वहन करना चाहिए था। चूँकि अपीलकर्ता ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया, इसलिए मामले को न्यायालय के मास्टर के पास भेजा गया, जो मद्रास उच्च न्यायालय शुल्क नियम, 1933 के तहत कर अधिकारी थे । मास्टर को लगा कि रजिस्ट्री द्वारा उठाया गया मुद्दा कुछ महत्वपूर्ण है और इसलिए, उन्होंने अपने कार्यकाल में उक्त विवाद को अधिनियम धारा ५ के तहत मूल पक्ष पर बैठे न्यायाधीश के पास भेज दिया। इस संदर्भ का निर्णय 18 अक्टूबर, 1951 को चैंबर न्यायाधीश कृष्णास्वामी नायडू जे. द्वारा

किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि अपीलकर्ता अपने पिता और प्रतिवादी के बीच पूर्व समझौता डिक्री को रद्द करने के लिए बाध्य नहीं था और वादपत्र अनुसूची २ के अनुच्छेद 17-बी. द्वारा शासित था । तदनुसार,विभाजन के लिए अपने दावे के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की गई अदालती फीस को उचित माना गया।

उचित समय पर प्रतिवादी को सूचित किया गया और उसने एक लिखित बयान दायर किया जिसमें विभाजन और खातों के लिए अपीलकर्ता के दावे के खिलाफ कई विवाद उठाए गए । प्रतिवादी द्वारा उठाए गए बिंदुओं में से एक यह था कि अपीलकर्ता के पिता द्वारा निष्पादित समझौता और रिहाई विलेख और बाद में पार्टियों के बीच पारित डिक्री निष्पक्ष और वास्तविक लेनदेन थे और चूंकि अपीलार्थी के पिता द्वारा वे विवादित दावे के निपटान के बराबर थे, वादी उनसे बंधा हुआ था।

मुकदमे की सुनवाई करने वाले रामास्वामी गौंडर जे. ने प्रारंभिक मुद्दे के रूप में समझौता डिक्री के बाध्यकारी चरित्र के बारे में प्रतिवादी के तर्क पर विचार किया। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि अपीलकर्ता के पिता ने अपनी शाखा के प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए विवाद का निष्पक्ष और प्रामाणिक समाधान किया था और इसलिए अपीलकर्ता समझौता डिक्री से बंधा हुआ था। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता का मुकदमा 22 सितंबर 1953 को खारिज कर दिया गया।

इस डिक्री के विरुद्ध अपीलकर्ता ने 1 दिसंबर, 1953 को अपना अपील ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस ज्ञापन में वादपत्र के समान ही न्यायालय शुल्क देना था। अपील के ज्ञापन की जांच करने पर रजिस्ट्री ने अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की गई फीस की पर्याप्तता पर फिर से सवाल उठाया। रजिस्ट्री ने यह विचार किया कि अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 7(v)के तहत और विभाजन के लिए अपने दावे के संबंध में न्यायालय शुल्क का भुगतान करना चाहिए था क्योंकि अपीलकर्ता का दावा वास्तव धारा 7(५) के अर्थ के तहत स्वामित्व के आधार पर कब्जे की वसूली का दावा था। फिर मामला मास्टर के पास भेजा गया लेकिन, अपनी बारी में, मास्टर ने फिर से अधिनियम की धारा 12(2) के तहत कराधान न्यायाधीश का संदर्भ दिया। इसके बाद विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस संदर्भ से निपटने के लिए दो न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया।

जिन विद्वान न्यायाधीशों ने सन्दर्भ सुना, उन्होंने इस पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा कि अधिनियम की धारा 12 वर्तमान अपील पर लागू थी या नहीं। उन्होंने अधिनियम की धारा ५ के तहत दिए गए संदर्भ से अपील का निपटारा कर दिया था। अपीलकर्ता ने डिवीजन बेंच के समक्ष आग्रह किया कि जस्टिस कृष्णास्वामी नायडू द्वारा पारित आदेश अंतिम था क्योंकि यह अधिनियम की धारा ५ के तहत पारित आदेश था। विद्वान न्यायाधीशों ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि रिकॉर्ड से यह नहीं पता चलता कि जस्टिस कृष्णास्वामी नायडू को

मुख्य न्यायाधीश द्वारा धारा ५ के तहत संदर्भ को सुनने के लिए किसी भी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नामित किया गया था और इसलिए धारा ५ के तहत उक्त आदेश के लिए कोई अंतिमता का दावा नही किया जा सकता है। गुण-दोष के आधार पर विद्वान न्यायाधीश कृष्णास्वामी नायडू द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हुए और माना कि अधिनियम की धारा 7(v) अपीलकर्ता के विभाजन के दावे पर लागू नहीं होती है। विद्वान न्यायाधीशों के अनुसार अनुसूची II का 17-बी लागू नही था। उन्होंने माना कि अधिनियम की धारा 7(iv)(बी) के प्रावधान लागू होते हैं। इसीलिए अपीलकर्ता को उक्त धारा के तहत विभाजन की राहत के लिए अपने मूल्य का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया था। इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह आदेश आवश्यक हो गया था क्योंकि वादपत्र में वादी ने अपने द्वारा दावा किए गए विभाजन की राहत के मूल्य का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने केवल यह कहा था कि उनके द्वारा दावा किए गए विभाजन की राहत के लिए वह अनुसूची II अनुच्छेद 17-बी के अनुसार 100 रुपये के न्यायालय शुल्क का भुगतान कर रहे थे। वाद पत्र में उसने जो कुछ किया वह क्षेत्राधिकार के लिए उसके कुल दावे का मूल्य रु. 15,00,000 था।

इस आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता ने मुकदमे में संयुक्त परिवार की संपत्तियों में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को लागू करने के लिए अपनी राहत का मूल्य 50,000 रूपये और घाटा अदालत शुल्क 1,662-7-0 रुपये

का भुगतान किया और 7 मई 1954 को अदालत में अपना अपील ज्ञापन प्रस्तुत किया।

हालाँकि, यह न्यायालय शुल्क के संबंध में वर्तमान विवाद का अंत नहीं था। इस बार रजिस्ट्री ने एक और आपत्ति जताई। रजिस्ट्री के अनुसार, चूंकि अपीलकर्ता ने क्षेत्राधिकार के मुकदमे में अपनी राहत का मूल्य 15,00,000, रूपये धारा के तहत अपील के ज्ञापन पर अपनी राहत का मूल्यांकन इसलिए वाद पत्र में किए गए मूल्यांकन में संशोधन के बिना धारा 7(iv)(बी) के तहत अपील के ज्ञापन पर अपनी राहत का मूल्य निर्धारण करना संभव नही था। चूंकि अपीलकर्ता ने रजिस्ट्री के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया, इसलिए मामले को फिर से आदेश के लिए अदालत के समक्ष रखा गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने उसकी राहत के क्षेत्राधिकार मूल्य के लिए 15,00,000 रूपये के स्थान पर 50,000 रूपये जोडकर अपनी याचिका में औपचारिक संशोधन के लिए आवेदन दायर करने की पेशकश की। तदनुसार अपीलकर्ता ने 18 अक्टूबर, 1954 को एक आवेदन किया। इस आवेदन का राज्य की ओर से प्रतिवादी और सहायक सरकारी वकील दोनों ने विरोध किया था। इस आवेदन पर सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीशों ने यह विचार किया कि यदि अपीलकर्ता ने अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए पहली बार में मूल्य दिया था तो उसे बाद के चरण में एक अलग मूल्य देने से रोक दिया गया था। तदनुसार यह माना गया कि रु. 15,00,000, जिसका उल्लेख वाद पत्र में न्यायिक

उद्देश्यों के लिए अपीलकर्ता के दावे के मुल्य के रूप में किया गया था, को अधिनियम की धारा 7(iv)(बी) के तहत न्यायालय शुल्क के प्रयोजनों के लिए अपीलकर्ता द्वारा दिए गए मूल्य के रूप में भी माना जाना चाहिए। परिणामस्वरूप वादपत्र में किए गए मूल्यांकन के औपचारिक संशोधन के लिए अपीलकर्ता द्वारा किया गया आवेदन खारिज कर दिया गया। विद्वान न्यायाधीशों ने अधिनियम की धारा 12(2) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कहा और निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को न केवल उनके अपील ज्ञापन पर बल्कि उनके वाद पत्र पर भी 15,00,000 रुपये के आधार पर घाटा न्यायालय शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह वह आदेश है जिसने वर्तमान अपील को जन्म दिया है।

अपीलकर्ता की ओर से श्री कृष्णास्वामी अयंगर ने हमारे सामने जो पहला मुद्दा उठाया है, वह यह है कि 18 अक्टूबर, 1951 को विद्वान चैंबर न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अधिनियम की 5 धारा के तहत अंतिम है। इस आदेश के द्वारा विद्वान चैंबर न्यायाधीश ने माना था कि वर्तमान मुकदमे में दायर वाद अधिनियम की धारा 7(v) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है और भुगतान किया जाने वाला उचित न्यायालय शुल्क अधिनियम की अनुसूची II के अनुच्छेद 17-बी द्वारा निर्धारित किया गया था। चूंकि अपीलकर्ता ने इस बाद वाले प्रावधान के तहत निर्धारित न्यायालय शुल्क 100 रुपये का भुगतान किया था, इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी कि पर्याप्त न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं

किया गया था । यदि यह आदेश वास्तव में अधिनियम की धारा 5 के तहत पारित किया गया होता तो यह निस्संदेह अंतिम होता। अधिनियम की धारा 5 न्यायालय शुल्क की आवश्यकता के संबंध में मतभेद की स्थिति में प्रक्रिया का प्रावधान करती है। ऐसे मामलों में जहां एक अधिकारी, जिसका कर्तव्य यह देखना है कि अध्याय III के तहत किसी भी शुल्क का भुगतान किया गया है, और शुल्क या उसकी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता के बारे में एक दावेदार के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो इसे उस कर अधिकारी को संदर्भित किया जाना चाहिए जिसका निर्णय है वहीं अंतिम होगा। यह धारा आगे प्रावधान करती है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी, जिसे कार्यालय द्वारा ऐसा अंतर भेजा गया है, की राय है कि उठाया गया मुद्दा सामान्य महत्व का है, तो वह उक्त बिंदु को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतिम निर्णय के लिए संदर्भित कर सकता है या मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को इस संबंध में आम तौर पर या विशेष रूप से नियुक्त किया जाएगा; और यह स्पष्ट है कि यदि मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसके लिए नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश संबंधित मामले का निर्णय करता है, तो उसका निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, दुर्भाग्य से, वर्तमान मामले में इस मामले से निपटने वाली डिवीजन बेंच द्वारा यह पाया गया कि रिकॉर्ड की खोज से कोई सामान्य या विशेष आदेश नहीं दिखा जो जस्टिस कृष्णास्वामी नायडू द्वारा धारा 5 के तहत क्षेत्राधिकार

के प्रयोग को उचित ठहराता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्णास्वामी अय्यंगार ने हमारे सामने कहा था कि मद्रास उच्च न्यायालय में मूल पक्ष और रजिस्ट्री के बीच उत्पन्न होने वाले उचित न्यायालय शुल्क के विवादों को हमेशा चैंबर न्यायाधीश के पास भेजने की परंपरा रही है और श्री अय्यंगार का कहना है कि हमेशा यह माना जाता था कि आम तौर पर ऐसे विवादों से निपटने के लिए चैंबर न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता था। वर्तमान मुकदमे से निपटने में ऐसी कोई भी धारणा बनाना हमारे लिए कठिन है। जब तक हम रिकॉर्ड से संतुष्ट नहीं हो जाते कि जस्टिस कृष्णस्वामी नायडू को भौतिक समय में धारा 5 के तहत कार्य करने के लिए आम तौर पर या विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। इस तर्क को स्वीकार करना कठिन होगा कि वर्तमान कार्यवाही में उनके द्वारा पारित आदेश अंतिम है। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि रिकॉर्ड धारा 5 के अनुसार कोई सामान्य या विशेष आदेश को नहीं दिखाता है। इसीलिए हमें यह मानना चाहिए कि डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने जस्टिस कृष्णास्वामी नायडू द्वारा पारित आदेश को अंतिम रूप देने से इनकार करके सही किया था।

इसके बाद श्री कृष्णास्वामी अय्यंगार ने आग्रह किया कि विद्वान न्यायाधीश अधिनियम की धारा 12(2) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में गलती कर रहे थे जब उन्होंने अपीलकर्ता को 15,00,000 रुपये के मूल्यांकन के आधार पर वादपत्र पर अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का

भुगतान करने का निर्देश दिया। उनका तर्क यह है कि धारा 12 मद्रास उच्च न्यायालय के मूल पक्ष के मुकदमों में पारित निर्णयों और डिक्री से उत्पन्न होने वाली अपीलों पर लागू नहीं होता है। यह बिल्कुल सच है कि उच्च न्यायालयों में उनके मूल पक्षों पर शुल्क लगाने का प्रश्न अधिनियम की धारा 3 द्वारा शासित होता है और यदि मामले को केवल अधिनियम के संदर्भ में तय किया जाना था, तो इसे लागू करना संभव नहीं होगा अधिनियम के अध्याय III में निहित किसी भी प्रावधान के अनुसार या तो मद्रास उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में मुकदमा दायर किया जाता है या निर्णयों और डिक्री से उत्पन्न होने वाली अपीलों के लिए। लेकिन यह सामान्य आधार है कि, मद्रास उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर वादों पर, अधिनियम के अध्याय III में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत न्यायालय शुल्क लगाया जाता है और इन शुल्कों की वसूली आदेश II, नियम 1 उच्च न्यायालय शुल्क नियम, 1933 द्वारा अधिकृत है। इसलिए, यह जांचना आवश्यक है कि अधिनियम के कौन से प्रावधान मूल पक्ष पर दायर मुकदमों तक बढ़ाए गए हैं। आदेश II का नियम I को अधिनियमित करने में मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार और क्षेत्राधिकार विवाद में नहीं है। हमारे सामने जो विवाद है वह उक्त नियम का प्रभाव है। अपीलकर्ता का मामला यह है कि उक्त नियम केवल कुछ निर्दिष्ट न्यायालय शुल्क लगाने पर विचार करता है जैसा कि अधिनियम के प्रावधानों में दर्शाया गया है जो स्पष्ट रूप से मूल पक्ष पर लागू होते हैं। अपीलकर्ता के

अनुसार, अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान को विस्तारित नहीं किया जा सकता है और इसलिए विद्वान न्यायाधीश धारा 12(2) के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में गलती कर रहे थे। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि यह तर्क उचित है।

आदेश II, नियम I इस प्रकार पढ़ा जायेगा :

> "मद्रास उच्च न्यायालय फीस नियम, 1933 का आदेश II, नियम 1:-
>
> आदेश II
>
> 1. परिशिष्ट II में निर्धारित शुल्क और कमीशन, जैसा भी मामला हो, रजिस्ट्रार, शेरिफ, भारतीय रिजर्व बैंक और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसमें निर्दिष्ट कई दस्तावेजों, मामलों और लेनदेन पर लिया जाएगा। सरकार से वसूला जाने वाला कमीशन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वसूला जाएगा और सरकार को जमा किया जाएगा। ∗(अपील के ज्ञापन सहित अन्य दस्तावेजों पर रजिस्ट्रार न्यायालय फीस से संबंधित उस समय लागू होने वाले

> कानून को लागू करेगा, जहां तक ऐसी फीस के पैमाने, ऐसी फीस लगाने के तरीके, रिफंड के संबंध में है, ऐसी फीस और हर अन्य संबंध में, उस तरीके से और उस सीमा तक, जिस तरह से यह जिला न्यायालय में मूल कार्यवाही में दायर किए गए समान दस्तावेजों और जिला न्यायालय के डिक्री और आदेशों के खिलाफ अपील में लागू होती है)।
>
> *1949 के आर.ओ. सी. नंबर 2219 द्वारा जोड़ा गया।"

इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि इस नियम के परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 7(iv) (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) प्रावधान के साथ-साथ अधिनियम की अनुसूची II अनुच्छेद 17-बी उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर मुकदमों पर लागू होता है। आदेश का उत्तरार्द्ध भाग जो 1949 में जोड़ा गया है, स्पष्ट रूप से अधिनियम के मूल प्रावधानों, फीस के पैमाने, उनके लगाने के तरीके और फीस की वापसी के संबंध में उच्च न्यायालय के प्रावधानों के मूल पक्ष पर मुकदमों और अपीलों पर लागू होता है। यह अधिनियम के प्रासंगिक "हर दूसरे संबंध" में भी लागू करता है। संदर्भ में "हर दूसरे संबंध में" शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि धारा 12 जो अपीलीय अदालत के प्राधिकारी या

क्षेत्राधिकार को न केवल अपीलकर्ता के ज्ञापन पर भुगतान की गई अदालती फीस की पर्याप्तता या अन्यथा के बारे में प्रश्न की जांच करने के लिए प्रदान करता है, बल्कि अपील की अदालत के समक्ष आने वाले मुकदमे में वादपत्र पर भी स्पष्ट रूप से इरादा रखता है। वादपत्रों और अपील के ज्ञापनों पर अदालती फीस लगाने के लिए अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करना और उस संबंध में भुगतान की गई अदालती फीस की पर्याप्तता या अन्यथा की जांच करने के लिए उपयुक्त अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करना वास्तव में अतार्किक होगा। अदालती फीस की वापसी के दावों पर विचार करने की शक्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। रिफंड के लिए दावा वैध रूप से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए ऐसे मामले में जहां अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया हो। इसीलिए धारा 13, धारा 14 और 15 के प्रावधान को शर्तों में लागू करना पड़ा। यदि कोई वादी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा शासित मामलों में न्यायालय शुल्क की वापसी के लिए दावा करने का हकदार है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्यायालय शुल्क के अपर्याप्त भुगतान के बारे में सवाल पर विचार करने के लिए अदालत को खुला न होना चाहिए। तार्किक रूप से, यदि भुगतान की गई अतिरिक्त अदालती फीस को इन कार्यवाहियों में वापस किया जाना चाहिए, तो भुगतान की गई अपर्याप्त या अपर्याप्त अदालती फीस को उसी आधार पर निपटाया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में घाटे की अदालती फीस का भुगतान करने के आदेश पारित किए जाने

चाहिए। यह इस प्रकार के मामले हैं जो स्पष्ट रूप से "हर दूसरे संबंध में" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किए गए हैं, जिनका हमने अभी उल्लेख किया है। इसलिए हम मानते हैं कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायाधीशों नें धारा 12 की उप-धारा 1 व 2 के तहत क्षेत्राधिकार ग्रहण करना उचित ठहराया है। धारा 12 दो भागों से मिलकर बनी है। उपधारा (1) में प्रावधान है कि वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर न्यायालय शुल्क के उचित भुगतान के बारे में प्रश्न उस न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा जिसमें ऐसा वादपत्र या अपील का ज्ञापन दायर किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह का निर्णय मुकदमे के पक्षों के बीच अंतिम होता है। उप-धारा (2) अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण न्यायालय को वादपत्र पर भुगतान की गई अदालती फीस की पर्याप्तता के प्रश्न से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, जब भी वह मुकदमा जिसमें ऐसा वाद दायर किया गया है, उसके समक्ष आता है और यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उचित अदालती शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वह एक आदेश पारित कर सकता है जिसमें पक्ष को इतनी अतिरिक्त फीस का भुगतान करने की आवश्यकता होगी जितनी कि यदि प्रश्न का पहली बार में सही निर्णय लिया गया होता तो देय होता। चूंकि जस्टिस कृष्णास्वामी नायडू का निर्णय अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित अंतिम निर्णय को आकर्षित नहीं कर सकता है, इसलिए यह डिवीजन बेंच के लिए यह खुला है कि वह विद्वान चैंबर न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर विचार करे और चूँकि वे

संतुष्ट थे कि वादपत्र अनुसूची II की अनुच्छेद 17-बी के अन्तगर्त नहीं आते है। धारा 12(1) और (2) तहत वे उचित आदेश पारित करने के हकदार थे

हालाँकि, अपीलकर्ता का तर्क है कि विद्वान न्यायाधीशों ने उसे उनके वादपत्र और अपील के ज्ञापन दोनों पर 15,00,000 रुपये के मूल्य के आधार पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देकर गलती की थी, क्योंकि उनका तर्क है कि यह निर्णय पहले के आदेश के साथ असंगत है कि अपील के ज्ञापन पर भुगतान की जाने वाली उचित अदालती फीस अधिनियम की धारा 7(iv)(बी) के तहत निर्धारित की जानी थी। यह आदेश डिविजन बेंच ने अधिनियम के 5 के तहत पारित किया है और यह पार्टियों के बीच अंतिम है। यह आदेश अपीलकर्ता को विभाजन की राहत के लिए अपने दावे का मूल्य निर्धारण करने की अनुमति देता है और 50,000. रुपये का मूल्य निर्धारण करके अपने विकल्प का प्रयोग करता है। इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा अदालती शुल्क के भुगतान के लिए विभाजन की राहत के मूल्य के संबंध में किया गया मूल्यांकन क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए भी मूल्यांकन माना जाना चाहिए और केवल इस मूल्यांकन पर ही अपीलकर्ता का मूल्यांकन किया जा सकता है। वादपत्र और अपील के ज्ञापन दोनों पर अदालती फीस का भुगतान करने के लिए उचित रूप से कहा गया। इसलिए, विद्वान न्यायाधीशों ने अपीलकर्ता को वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति नहीं देकर गलती की ताकि वादपत्र को

अधिनियम की धारा 7, उप-धारा (iv) के प्रावधानों के अनुरूप लाया जा सके। संक्षेप में यह अपीलकर्ता का मामला है।

दूसरी ओर, मद्रास के हस्तक्षेपकर्ता महाधिवक्ता की ओर से और साथ ही प्रतिवादी की ओर से, हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया था कि। अधिनियम की धारा 7(v) के तहत न्यायालय शुल्क के भुगतान के उददेश्य से वाद पत्र व अपील के ज्ञापन का मुल्य निर्धारण किया जाना चाहिए यह माना जाता है कि अदालती फीस के सवाल पर वादपत्र में लगाए गए आरोपों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए और इसका निर्णय लिखित बयान में दी गई दलीलों या योग्यता के आधार पर मुकदमे के अंतिम निर्णय से प्रभावित नहीं हो सकता है। हालाँकि, तर्क यह है कि यदि वादपत्र में निहित सभी भौतिक आरोपों को निष्पक्ष रूप से समझा जाए और समग्र रूप से लिया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि वादी को मुकदमे में संपत्तियों के आनंद से बेदखल कर दिया गया है और विभाजन के लिए उसका दावा वास्तव में एक है। मुकदमे की संपत्तियों पर कब्जे का दावा और इस तरह के प्रावधान अधिनियम की धारा 7 की उपाधारा (v) के अंतर्गत आते हैं। जिन वादपत्रों में हिंदू वादी अलग-अलग परिस्थितियों में विभाजन के लिए दावा करते हैं, उन पर लगाए जाने वाले उचित अदालती शुल्क के सवाल ने भारत के उच्च न्यायालयों में कई परस्पर विरोधी निर्णयों को जन्म दिया है। हालाँकि, हमें इस बिंदु पर विचार करने के लिए नहीं कहा गया है कि क्या धारा 7(v) वर्तमान वाद पर लागू होगी या क्या

वर्तमान वाद धारा 7(iv)(बी) के अंतर्गत आएगा। हमारी राय में, मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय कि अपील के ज्ञापन पर अधिनियम की धारा 7(iv)(बी) के तहत अदालती शुल्क के प्रयोजनों के लिए कर लगाया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के तहत का अंतिम है और इसे इस स्तर पर फिर से नहीं खोला जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर मास्टर द्वारा धारा 5 के तहत किए गए संदर्भ में विचार किया हो, प्रतिवादी की बात नहीं सुनी गई हो। आम तौर पर कोर्ट फीस के संबंध में वादी और रजिस्ट्री के बीच विवाद वाद या अपील की प्रस्तुति के प्रारंभिक चरण में उठता है और प्रतिवादी या प्रत्यर्थी को आमतौर पर ऐसे विवाद में कोई दिलचस्पी नहीं होती है जब तक कि अदालती फीस के भुगतान का सवाल न हो। इसमें मुक़दमे की सुनवाई करने या अपील पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न भी शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता के अपील के ज्ञापन पर लगाए जाने वाले अदालती शुल्क की पर्याप्तता के बारे में प्रश्न मास्टर द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश को उचित रूप से भेजा गया था और उक्त उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा निर्णय लिया गया है। ऐसे मामले में मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में दिए गए अपेक्षित आदेश के अनुसरण में। डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए निर्णय को अधिनियम की धारा 5 के तहत अंतिम माना जाना चाहिए। इसीलिए हमने फिलहाल इस आदेश

की खूबियों पर सवाल नहीं उठाने दिया है। इसलिए, हमें अपीलकर्ता के तर्क को इस आधार पर निपटाना चाहिए कि अपील के ज्ञापन पर अदालत की फीस अधिनियम की धारा 7(iv) (बी) के तहत लगाई जानी चाहिए।

जिस प्रश्न पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता को 15,00,000 रुपये के मूल्यांकन के आधार पर वादपत्र और अपील के ज्ञापन दोनों पर अदालती शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देना सही था। हमारी राय में अपीलकर्ता का यह तर्क उचित है कि यह आदेश कानून की दृष्टि से गलत है। धारा 7 की उप-धारा (iv)(बी) किसी भी संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार को इस आधार पर लागू करने के लिए मुकदमों से निपटता है कि यह संयुक्त परिवार की संपत्ति है और ऐसे मुकदमों में वादपत्रों पर देय शुल्क की राशि "उस राशि के अनुसार है जिस पर राहत मांगी गई है" वादपत्र या अपील के ज्ञापन में मूल्यांकित है।" धारा 7 में आगे प्रावधान है कि धारा 7(iv) के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों में वादी को वह राशि बतानी होगी जिस पर राहत की कीमत मांगी गई है। यदि मुकदमों में देय शुल्क की गणना के लिए निर्धारित योजना धारा 7 के कई उप-अनुभागों द्वारा कवर जाती है तो उस पर विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि, उप-धाराओं (iv) के अंतर्गत आने वाले मुकदमों के संबंध में एक प्रस्थान किया गया है और वादी को अदालती शुल्क के प्रयोजनों के लिए अपने दावे का मूल्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रावधान का सैद्धांतिक आधार यह प्रतीत

होता है कि जिन मामलों में वादी को अपने दावे का मूल्य निर्धारण करने का विकल्प दिया जाता है, किसी भी सटीकता या निश्चितता के साथ दावे का मूल्य निर्धारण करना वास्तव में कठिन होता है। उदाहरण के लिए विभाजन के दावे को लें जहां वादी किसी संपत्ति में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को इस आधार पर लागू करना चाहता है कि यह संयुक्त परिवार की संपत्ति है। दावे का आधार यह है कि जिस संपत्ति के संबंध में हिस्सेदारी का दावा किया गया है वह संयुक्त परिवार की संपत्ति है। दूसरे शब्दों में, यह वह संपत्ति है जिसमें वादी का अविभाजित हिस्सा होता है। विभाजन के लिए दावा करने से अभियोगी का अभिप्राय यह है कि वह अदालत से पूरी संपत्ति में अपने अविभाजित हिस्से के बदले में कुछ निर्दिष्ट संपत्तियों को अलग से और पूरी तरह से अपने खाते में देने के लिए कहे। अब यह स्पष्ट हो जाएगा कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में वादी के कथित अविभाजित हिस्से को उसके अलग हिस्से में बदलने का मूल्य आसानी से किसी भी सटीकता या निश्चितता के साथ रुपये के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए विधायिका ने अदालती शुल्क के भुगतान के लिए अपने दावे का मूल्य निर्धारण वादी के विकल्प पर छोड़ दिया है। इसका वास्तव में मतलब है कि धारा 7 (iv)(बी) के अंतर्गत आने वाले सूट में वादी द्वारा विभाजन के लिए अपने दावे के मूल्य के रूप में बताई गई राशि को आमतौर पर उक्त राहत के संबंध में देय अदालती फीस की गणना करते समय अदालत द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इस मामले की

परिस्थितियों में यह विचार करना अनावश्यक है कि क्या, इस धारा के प्रावधानों के तहत, वादी को अपनी राहत पर कोई भी मूल्यांकन करने का पूर्ण अधिकार या विकल्प दिया गया है।

ऐसे मुकदमों में क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिए क्या मूल्य होगा यह एक और प्रश्न है जो अक्सर निर्णय के लिए उठता है। इस प्रश्न का निर्णय अधिनियम की धारा 7 (iv) को सूट मूल्यांकन अधिनियम की धारा 8 सहित पढ़कर करना होगा। यह बाद वाला खंड यह प्रदान करता है कि, जहां कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7, पैरा 5, 6 और 9 और पैरा. 10 सीएल. (डी), में संदर्भित मामलों के अलावा किसी भी मुकदमे में अदालती फीस यथामूल्य देय है। अदालती फीस की गणना के लिए निर्धारित मूल्य और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मूल्य समान होगा। दूसरे शब्दों में, जहां तक मुकदमें जो अधिनियम की धारा 7 उप-धारा (iv) के अंतर्गत आते हैं, सूट वैल्यूएशेन एक्ट की धारा 8 में प्रावधान है कि अदालती फीस की गणना के लिए निर्धारित मूल्य और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मूल्य समान होगा। इसमें थोड़ा संदेह हो सकता है कि धारा 8 के प्रावधानों का प्रभाव उद्देश्य क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिए मूल्य को अदालती शुल्क की गणना के लिए निर्धारित मूल्य पर निर्भर बनाना है और यह काफी स्वाभाविक है। अधिनियम की धारा 7 (iv) के अंतर्गत आने वाले मुकदमों में न्यायालय शुल्क की गणना वादी द्वारा अपने दावे के संबंध में किये गये मूल्यांकन पर निर्भर करती है। एक बार जब वादी अपने विकल्प का प्रयोग

करता है और अदालती शुल्क के प्रयोजन के लिए अपने दावे को महत्व देता है, तो वह क्षेत्राधिकार के लिए मूल्य निर्धारित करता है। ऐसे मामलों में अदालती फीस का मूल्य और क्षेत्राधिकार का मूल्य निस्संदेह समान होना चाहिए; लेकिन वादी द्वारा बताई गई अदालती फीस का मूल्य प्राथमिक महत्व का है। इसी मूल्य से न्यायक्षेत्र का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। नतीजा यह है कि यह वह राशि है जिस पर वादी ने अदालती शुल्क के प्रयोजनों के लिए मांगी गई राहत का मूल्य निर्धारण किया है जो मुकदमे में क्षेत्राधिकार के लिए मूल्य निर्धारित करता है, न कि इसके विपरीत। संयोग से हम बता सकते हैं कि अपीलकर्ता के अनुसार वर्तमान मामले में क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन के रूप में 15,00,000 रुपये का उल्लेख करना वास्तव में आवश्यक नहीं था। क्योंकि वाद पत्र 1953 से पहले मद्रास उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर किया गया था इसलिए कोई क्षेत्राधिकार मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी।

वादी द्वारा यह बताने में विफलता कि वह किस राशि पर मांगी गई राहत को महत्व देता है, अक्सर इस तथ्य के कारण होता है कि विभाजन के मुकदमों में वादी न्यायालय शुल्क के भुगतान के मामले में अनुसूची II की अनुच्छेद 17-बी का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। जहां वादी उक्त अनुच्छेद के अनुसार निर्धारित न्यायालय शुल्क का भुगतान करना चाहता है, वहां उसका और उसके सलाहकारों का मानना है कि न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए दावा करने के लिए उस राशि का उल्लेख करना

अनावश्यक है जिसके लिए राहत की मांग की गई है। इसलिए, केवल अधिकार क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है। अक्सर, यह पता चलता है कि वादपत्र अनुसूची II के अनुच्छेद 17-बी के प्रावधानों को सख्ती से आकर्षित नहीं करता है और अदालत शुल्क का भुगतान या तो अधिनियम की धारा 7(iv)(बी) के तहत या अधिनियम की धारा 7(v) के तहत किया जाना है। यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामला धारा 7(iv)(बी) या धारा 7(iv)(सी) के अंतर्गत आता है आम तौर पर वादी को अपनी याचिका में संशोधन करने और विशेष रूप से वह राशि निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिस पर वह अदालती शुल्क के भुगतान के लिए अपने दावे का मूल्य निर्धारित करना चाहता है। ऐसे मामले में यह उचित या सही नहीं होगा कि वादी को अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा किए गए मूल्यांकन से बाध्य रखा जाए और यह निष्कर्ष निकाला जाए कि उक्त मूल्यांकन को अदालती शुल्क के भुगतान के लिए मूल्यांकन के रूप में भी लिया जाना चाहिए। इस संबंध में हम बता सकते हैं कि करम इलाही बनाम मुहम्मद बशीर (1) (एआईआर (1949) लाहोर 116. मामले में लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है। सूट वैल्यूएशन एक्ट की धारा 8 में कहा गया है कि वादी को पहले अदालती शुल्क के उद्देश्य से अपने दावे का मूल्यांकन करना चाहिए और यह ऐसे दावे के आधार पर क्षेत्राधिकार के मूल्य के निर्धारण का

प्रावधान करता है। इसलिए हमारी राय में विद्वान न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि वादपत्र में दिखाए गए क्षेत्राधिकार के मूल्यांकन को वादपत्र पर अदालती शुल्क के भुगतान के साथ-साथ अपील के ज्ञापन के मूल्यांकन के रूप में लिया जाना चाहिए। उनके पूर्व निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामला धारा 7(iv)(बी) के अंतर्गत आता है, उन्हें अपीलकर्ता को न केवल अपील के ज्ञापन पर बल्कि वादपत्र पर भी अदालती शुल्क के भुगतान के लिए अपने मूल्यांकन में संशोधन करने की अनुमति देनी चाहिए थी। हमें तदनुसार अपील के तहत आदेश को रद्द करना चाहिए और निर्देश देना चाहिए कि वादी को 50,000 रुपये की राशि बताने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिस पर वह अधिनियम की धारा 7(iv)(बी) के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा मांगी गई राहत को महत्व देता है। श्री कृष्णास्वामी अयंगर ने हमसे मौखिक रूप से अनुरोध किया है कि उन्हें अपनी याचिका में उचित संशोधन करने की स्वतंत्रता दी जाए और हमने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

परिणामस्वरूप अपील की अनुमति दी जाएगी और अपीलकर्ता को 50,000 रुपये के मूल्यांकन के आधार पर अपने वादपत्र पर आज से दो महीने के भीतर अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा। चूंकि अपीलकर्ता ने पहले ही अपने अपील ज्ञापन पर पर्याप्त अदालती शुल्क का भुगतान कर दिया है, इसलिए इस संबंध में कोई और

आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

अपील स्वीकार की जाती है

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **सुश्री शैल कुमारी सोलंकी** (आर.जे.एस.) के द्वारा किया गया है

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्दश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा